3 अर्थव्यवस्था को मजबूती के लिए है मनरेगा

5 छात्र राजनीति से भारत सरकार के प्रमुख पदों तक

8 फलीभूत हुआ एकता का महाकुम्भ

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 15 अंक : 43 प्रति सोमवार, 3 मार्च 2025 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनते ही उज्जैन की पत्रकार रेखा गोस्वामी गायब, रेखा गोस्वामी के घरवालों ने करायी गायब होने की एफआईआर दर्ज, गायब होने के पहले रेखा गोस्वामी ने जताई थी हत्या की आशंका

रेखा गोस्वामी ने अपने अखबार अभय आवाज में प्रकाशित की थी मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार की खबरें

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

पत्रकार समाज का आईना होता है। समाचार प्रकाशित, प्रसारित करना इनका संवैधानिक अधिकार है, जिसकी सुरक्षा आज खतरे में है। पुलिस प्रशासन सुरक्षा प्रदान करने में पूर्ण रूप से असमर्थ होकर स्वयं झूठे प्रकरण दर्ज कर राजनेताओं को प्रसन्न करने में व्यस्त है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पूरे प्रदेश सहित उज्जैन के पत्रकारों को परेशान करने में लगे हुए हैं। पत्रकारिता पर पहरा लगाकर

मोहन यादव अपने आप को तानाशाह बना रहे हैं और लोकतंत्र का गला घोंटने पर लगे हैं। प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि पत्रकारों के खिलाफ खुले रूप में अत्याचार और अनाचार किया जा रहा है।

हाल ही में सबसे भयभीत और विचलित करने वाला मामला सामने आया है। यह मामला है उज्जैन की पत्रकार रेखा गोस्वामी का। रेखा गोस्वामी उज्जैन की दबंग पत्रकार हैं। अपने साप्ताहिक अखबार अभय आवाज में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी की खबरें प्रकाशित करती रही हैं। लेकिन रेखा गोस्वामी की साहसी पत्रकारिता से कई लोग परेशान होते रहे हैं। इनमें से एक नाम वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी है। मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने से पहले रेखा गोस्वामी ने अपने अखबार में इनके खिलाफ भ्रष्टाचार की काफी खबरें प्रकाशित की थी। लेकिन जैसे ही मोहन यादव मुख्यमंत्री बने उन्होंने एक-एक कर अपने खिलाफ लिखने वालों को ठिकाने लगाने का काम शुरू किया। उनमें रेखा गोस्वामी भी हैं। रेखा गोस्वामी मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से गायब है। वह कहां है, किस हालात में हैं और जिंदा भी हैं कि नहीं, किसी को पता नहीं है। वह पिछले 15 महीने से गायब है। उनके घरवालों ने उज्जैन के थाने में गायब होने की एफआईआर भी दर्ज की है। अब तो घरवालों को रेखा की चिंता सताने लगी है। यहां तक कि वह इस विषय में भी बात करने से कतराते हैं और डरते हैं। (शेष पेज 2 पर)

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत बनाने दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ के जनकल्याण के लिये समर्पित होकर कार्य कर रहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार प्रदेश की जनता के हितों में महत्वपूर्ण फैसले ले रहे हैं। मुख्यमंत्री साय का मानना है कि यदि जनता खु श हा ल रहेगी तो प्रदेश की प्रगति उसी गति से होगी। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने किसानों और

दुग्ध उत्पादकों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिये पहली बार डेयरी उद्योग को मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कहा कि छत्तीसगढ़ में श्वेत क्रांति की तर्ज पर डेयरी उद्योग को सशक्त बनाने और किसानों व पशुपालकों की आय दोगुनी करने की दिशा में राज्य सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन को लाभकारी व्यवसाय बनाने और प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के सहयोग से एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसके तहत व्यापक स्तर पर कार्य किया जाएगा। जाहिर है कि दिसंबर 2024 में राज्य सरकार और NDDB के बीच हुए समझौते के बाद छत्तीसगढ़ में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। (शेष पेज 5 पर)

मोहन सरकार के लिए वर्चस्व का मुद्दा बन गया है ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा

-विजया पाठक

पिछले दिनों मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू न किये जाने वाली याचिका को निरस्त कर दिया था। कोर्ट ने प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने को अपनी सहमति दे दी थी। लेकिन अब वर्तमान डॉ. मोहन यादव की सरकार हाईकोर्ट के फैसले की अवमानना करते हुए प्रदेश में आरक्षण लागू न करने पर अडिग है। यही नहीं मोहन सरकार कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिये तैयार है। जाहिर है यह पूरा मामला मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के समय का है। कमलनाथ ने लाखों युवाओं के सपनों को पूरा करने और उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में एक कदम

बढ़ाते हुए प्रदेश में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किये जाने का फैसला किया था। लेकिन सिंधिया की गद्दारी के कारण कमलनाथ की सरकार चली गई और बाद में मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले को कानूनी दांवपेंच में ऐसा तोड़ा मरोड़ा कि कोर्ट में पूरा मामला लगभग चार साल तक चला। (शेष पेज 2 पर)

MP में बीजेपी अध्यक्ष की सुगबुगाहट तेज:

डॉ. नरोत्तम मिश्रा को मिल सकती है प्रदेश भाजपा की कमान

(विस्तृत पेज 5 पर)

मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनते ही उज्जैन की पत्रकार रेखा गोस्वामी गायब

(पेज 1 से जारी)

पत्रकार रेखा गोस्वामी ने जताई थी हत्या की आशंका

रेखा गोस्वामी एक महिला पत्रकार हैं तथा फ्रीगंज (उज्जैन) में निवास करती हैं। इनके पास साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र अभय आवाज का प्रकाशन स्वामित्व व संपादक की जिम्मेदारी है। गायब होने से पहले रेखा गोस्वामी ने अपनी हत्या की आशंका जताई थी। क्योंकि मुख्यमंत्री बनने से पहले मोहन यादव के खिलाफ काफी कुछ प्रकाशित किया था। शायद रेखा को तब से ही अपनी हत्या की आशंका हो गई होगी। एक वाक्या है जो रेखा ने बताया था, जो इस प्रकार है- 16 नवंबर 2023 को ईदौर रोड पर हॉकर्स द्वारा साप्ताहिक अखबार अभय आवाज का वितरण किया जा रहा था। महामृत्युंजय गेट से हॉकर लौट रहे थे तभी बीच सड़क पर वार्ड क्रमांक 48 के बीजेपी पार्षद अंशु अग्रवाल के पति गोपाल अग्रवाल, कार्तिक मिश्रा, अजय शुक्ला, सचिन वर्मा, सोनू बिजोलिया, सतीश सिंदल, गजेंद्र खत्री, प्रकाश जायसवाल और अन्य लोग आए और दोनों हॉकर के साथ रास्ता रोककर मारपीट की और गालियां देते हुए बोले हमारे खिलाफ छापकर अखबार बेचते हो। इन लोगों ने अखबार का बंडल लूट लिया और गाड़ियों में तोड़फोड़ कर चाबियां भी ले गए। इस दौरान जब लोग इनका वीडियो बनाने लगे तो जाते-जाते उन्होंने धमकी दी कि हमारे खिलाफ छापा तो जान से मार देंगे। ये सभी लोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। इनके

खिलाफ केस दर्ज हैं। इनसे रेखा गोस्वामी व इनके साथियों को जान का खतरा था। रेखा गोस्वामी ने पुलिस अधीक्षक उज्जैन से सुरक्षा प्रदान की मांग करते हुए कहा था कि यह लोग कभी भी मुझ पर हमला कर सकते हैं। रेखा गोस्वामी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से संबंधित तथ्यात्मक खबर अपने अखबार अभय आवाज में प्रकाशित की थी। इसलिए डॉ. मोहन यादव गुट के कुछ लोग इनसे रंजिश रखते हैं। रेखा गोस्वामी द्वारा अपने समाचार पत्र में मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ शासकीय भूमि पर अवैधानिक रूप से कब्जा करने एवं उस पर अपना निजी अस्पताल निर्मित कर संचालित करने के संबंधित प्रमाण प्राप्त होने के समाचार प्रकाशित किए गए थे। इनके अलावा अन्य कई पत्रकारों ने भी इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित प्रसारित किए गए थे। जिस कारण मोहन यादव उनके खिलाफ समाचार पत्र छापने वाले पत्रकारों के विरुद्ध द्वेष की भावना रखते हुए अपने पद का दबाव उज्जैन पुलिस पर बना कर पत्रकारों के विरुद्ध झूठे प्रकरण बनवा रहे हैं। पत्रकार राजीव भदौरिया और मनीष भालसे के विरुद्ध झूठे मुकदमे लगवाए गए हैं। पत्रकार ऋषि शर्मा राज रॉयल कालोनी उज्जैन स्थित अपने घर पर थे। इस दौरान तीन बाइक पर सवार आधा दर्जन बदमाश पहुंचे। उनके हाथ में थैला भरकर पत्थर थे। उन्होंने आते ही गालियां देना शुरू कर दी। इसके बाद सभी ने घर पर पत्थर बरसाए। दो बदमाश सीसीटीवी पर पत्थर मारते रहे। बदमाश जाते समय जान से मारने की धमकी भी दे गए। पत्रकार इंद्रेश सूर्यवंशी कवरेज करने के लिए उज्जैन जिले के तराना जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में उनकी कार को मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने जानबूझकर टक्कर मारकर रोक दिया। इसके बाद जब इंद्रेश में बदमाशों को समझाने की कोशिश की तो वे उन पर टूट पड़े। आरोपियों ने लाठी से पत्रकार पर हमला किया। इस घटना की शिकायत करने के लिए जब पत्रकार इंद्रेश तराना थाने पहुंचा तो वहां पुलिसकर्मियों ने भी ध्यान नहीं दिया। इसके बाद उज्जैन एसपी के पास मामला पहुंचा। हाल ही में उज्जैन पुलिस ने पत्रकार राजेंद्र सिंह भदौरिया, रेखा गोस्वामी, जय कौशल, शकील खान व समेत अन्य पत्रकारों को काफी परेशान किया। इन पर ब्लैकमेलिंग और लूट की धाराओं में केस दर्ज करवा दिये हैं।

उज्जैन के करीब 8-9 पत्रकार हैं जिन्होंने मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के पहले इनके कारनामों को उजागर किया था। उन्हें मोहन यादव ने गलत आरोप लगाकर या तो जेल में डलवा दिया था या जिलाबदर करवा दिया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एक पत्रकार मोहन यादव के अत्याचारों के कारण घर बार छोड़कर कहीं चला गया है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि कहीं उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई।

ये हमलावर लोग मोहन यादव से जुड़े हुए लोग हैं तथा उज्जैन पुलिस दबाव में बिना किसी जांच के जबरन असत्य मामलों में प्रकरण दर्ज कर रही है और गिरफ्तार तक कर रह है, जिससे पत्रकार प्रताड़ित होकर भयभीत हैं।

सीएम यादव पर दिग्विजय सिंह ने लगाए ये आरोप

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पिछले दिनों ट्वीट करते हुए कहा था कि "मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने गृह नगर में कुछ मीडियाकर्मियों को टारगेट कर रहे हैं। हालांकि पुलिस और जिला प्रशासन ने पिछले तीन दशक के आपराधिक रिकॉर्ड जारी करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मंशा जाहिर कर दी थी।

कलम की ताकत को दबा रहे मोहन यादव

जमीनों पर कब्जा कर लेना, उन्हें बेदखल कर देना यह सब कृत्य करने के बाद यदि कोई पत्रकार कलम के माध्यम से जनता के सामने सच लाने का कार्य करता है तो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उस पर प्रशासकीय ढंग से लगाम लगाने का कार्य करते हैं। मोहन यादव की यह कार्यशैली मध्यप्रदेश के इतिहास के अब तक के मुख्यमंत्रियों में बिल्कुल अलग है जो कलम की ताकत को दबाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मोहन यादव मप्र में प्रजातंत्र खत्म करने की ओर अग्रसर हैं। जैसा उन्होंने उज्जैन और उसके आसपास के पत्रकारों के साथ व्यवहार किया है क्योंकि उन पत्रकारों ने मुख्यमंत्री बनने के पहले जमीन संबंधी घोटाले को अपने पेपर में छापा था। उनके उपर झूठे मुकदमें लगाकर जेल में बंद कर दिया। उससे साफ प्रतीत होता है कि मोहन यादव लिखने बोलने और छापने की स्वतंत्रता पर प्रहार कर रहे हैं। उनका यह रवैया अभिनायकवाद को दर्शाता है।

पिछले एक साल में ही करीब दो दर्जन पत्रकारों पर झूठी एफआईआर दर्ज करवाकर जेल में डाल दिया गया है। इतना ही नहीं कई पत्रकारों को तो जिलाबदर तक करवा दिया है। जिला प्रशासन इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए मकान तोड़ने की कार्रवाई कर रहा है। यही वजह है कि आज प्रदेश के पत्रकार दहशत में जीने को मजबूर हैं।

हाईकोर्ट की अवमानना का दुस्साहस करने वाले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

(पेज 1 से जारी)

लेकिन अब जब हाईकोर्ट ने मामले में हरी झंडी दे दी है तो मोहन सरकार अब इसके आड़े आ रही है। कुल मिलाकर भाजपा और उसके नेताओं का एक ही उद्देश्य है कि वह प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के विरोध में है और हर बार कानूनी दांव-पेंच लगाकर फैसले के आगे रोड़ा बनकर खड़े हो रहे हैं। खास बात यह है कि डॉ. मोहन यादव की सरकार लगातार शासकीय नौकरियों में आरक्षण का प्रतिशत सिर्फ 14 प्रतिशत अभी भी अपना रही है, जो कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। अब देखने वाली बात यह है कि कोर्ट के आदेश को न मानने के बदले में कोर्ट मोहन सरकार को क्या सजा सुनाती है और इसका क्या परिणाम मिलता है।

श्रेय पाने की होड़ और कानूनी दांव पेंच

राजनैतिक विश्लेषकों के अनुसार मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किये जाने का मामला पूरी तरह से श्रेय पाने की होड़ से जुड़ गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा बिल्कुल नहीं चाहती कि प्रदेश में आरक्षण लागू किये जाने का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को मिले। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के

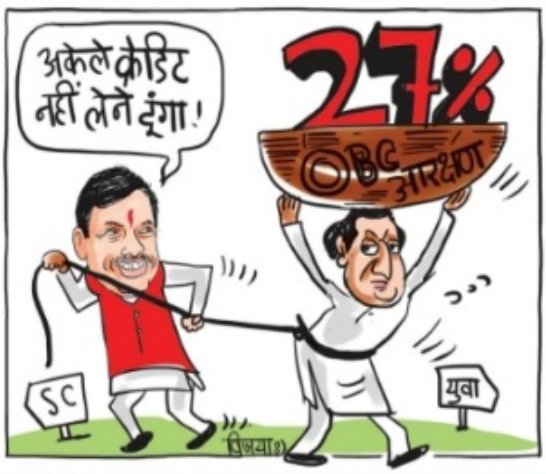

लाखों युवाओं के सपनों को पंख लगाने वाले कमलनाथ को श्रेय देने से आखिर क्यों पीछे हट रही भाजपा?

नेता और कानूनी सलाहकार इस पूरे मामले को हर बार कानूनी रूप से उलझाए रखे हुए ताकि चुनाव के ठीक पहले प्रदेश में आरक्षण लागू कर इसका श्रेय प्राप्त किया जा सके।

हकीकत कुछ और ही कहती है

अगर हम प्रदेश में आरक्षण लागू किये जाने वाले मामले के इतिहास पर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि प्रदेश में आरक्षण लागू किये जाने की पहल से लेकर संघर्ष हर समय पहला कदम पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बढ़ाया। उन्हीं की पहल के बाद राज्य में आरक्षण लागू किये जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ी और जब विधानसभा पटल पर बिल पेश हुआ तो भाजपा नेताओं ने कीचड़ मचाकर लाखों युवाओं के सपनों को चकना चूर कर दिया और पूरा मामला कानूनी रूप से कोर्ट के शिकंजे में चला गया।

पांच साल के इंतजार के बाद मिली थी जीत

कमलनाथ पर चुनाव से पूर्व ही जनता ने भरोसा दिलाया था कि इस बार वे ही सत्ता में आयेंगे। जनता के इस भरोसे पर खरा उतरते हुए कमलनाथ ने भी कहा था कि वे सत्ता संभालते ही आरक्षण का मुद्दा उठायेंगे और उसे लागू करेंगे। उसके बाद सत्ता में आते ही कमलनाथ ने अपनी बात पर कायम रहते हुए आरक्षण का विषय उठाया और प्रदेश में आरक्षण लागू करने की योजना पर कार्य शुरू किया।

मेरे फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई मुहरः कमलनाथ

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस विषय पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य शासन द्वारा प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण देने के फैसले का विरोध किया गया था। यह कांग्रेस पार्टी की नीतियों की जीत है। मार्च 2019 में मैंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में मध्य प्रदेश के ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया था। हाई कोर्ट के फैसले ने मेरी तत्कालीन सरकार के निर्णय को एक बार फिर सही साबित किया है। अब मध्य प्रदेश सरकार को तत्काल सभी स्तर पर 27% ओबीसी आरक्षण देना सुनिश्चित करना चाहिए। कमलनाथ ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा ने हमेशा षड्यंत्रकारी रवैया अपनाया है। अगर पिछले 06 साल के घटनाक्रम को देखें तो यह बात और ज्यादा स्पष्ट हो जाती है।

वर्तमान राज्य सरकार की जिम्मेदारी है

कमलनाथ ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि तुरंत सभी भर्तियों में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने के प्रावधान किए जाएं। मैंने और कांग्रेस सरकार ने ओबीसी को जो 27 प्रतिशत आरक्षण का अधिकार दिया था उसे सुनिश्चित करना वर्तमान राज्य सरकार की जिम्मेदारी है

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मनरेगा की है महत्वपूर्ण भूमिका: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

मुख्यमंत्री साय ने मनरेगा कार्यों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध रूप से पूरा करने के दिए निर्देश

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक विधानसभा परिसर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में मनरेगा कार्यों को सर्वोच्च गुणवत्ता और निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए, ताकि अधिकतम ग्रामीण परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री साय ने विशेष रूप से गांवों में धरसा पहुंच मार्ग निर्माण और अमृत सरोवर परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए, जिससे ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूती मिले और जल संरक्षण को बढ़ावा मिले। मुख्यमंत्री साय ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का

लक्ष्य केवल रोजगार देना नहीं, बल्कि ग्रामीण इलाकों को आत्मनिर्भर बनाना है। मनरेगा के तहत चल रही योजनाओं को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से लागू किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, ताकि यह योजना गरीबों के सशक्तिकरण में एक मजबूत आधार बने। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मनरेगा को अन्य योजनाओं से जोड़कर ग्रामीण विकास की गति तेज करने पर जोर दिया जा रहा है।

राज्य में मनरेगा के प्रभावशाली क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा

बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 की प्रगति, लेबर बजट 2025-26, योजना के प्रमुख इंडिकेटर्स और अभिसरण (कॉन्वर्जेंस) मॉडल पर गहन समीक्षा की गई। वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। मनरेगा आयुक्त रजत बंसल ने जानकारी दी कि प्रदेश में कुल 38.52 लाख पंजीकृत परिवारों में से 24.89 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया है। अमृत सरोवर योजना के तहत 2,902 जलाशयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 1,095 स्वीकृत हो चुके हैं, 299 पूर्ण हो चुके हैं, और 472 पर कार्य प्रगति पर है। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजू एस, पी. दयानंद, राहुल भगत, मनरेगा आयुक्त रजत बंसल एवं छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के सदस्यगण उपस्थित थे।

नगर निगम रायपुर के नव निर्वाचित महापौर एवं पार्षदों का शपथ ग्रहण

रायपुर को स्वच्छ, सुव्यवस्थित एवं समृद्ध शहर बनाने की दिशा में दृढ़ संकल्प के साथ करें कार्यः मुख्यमंत्री

-आनंद शर्मा

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में नगर पालिक निगम, रायपुर के नव निर्वाचित महापौर एवं पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में संपन्न हुआ। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने महापौर एवं सभी पार्षदों को वार्डवार शपथ दिलाई। महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में शपथ ग्रहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी नव-निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया

कि नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदगण अटल विश्वास पत्र में किए गए प्रत्येक वादे को पूरा कर रायपुर को स्वच्छ, सुव्यवस्थित एवं समृद्ध शहर बनाने की दिशा में दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करेंगे। शपथ ग्रहण उपरांत महापौर मीनल चौबे ने मुख्यमंत्री साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, मंत्रीगण, पूर्व महापौर एवं विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। समारोह में वन मंत्री केदार कश्यप, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक राजेश मूणत, किरण देव, सुनील सोनी, मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, अनुज शर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने सभी अतिथियों, जनप्रतिनिधियों एवं शहरवासियों का आभार व्यक्त किया।

ग्रामीण अंचलों में लगातार बढ़ रहे मादक पदार्थों के अवैध कारोबार, अंकुश हो रहा है बेअसर

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। जिले के ग्रामीण अंचलों में मादक पदार्थों का अवैध कारोबार लगातार बढ़ता रहा है। बताया जाता है कि शराब के बाद ग्रामीण अंचलों मे अन्य नशीले चीजों की विक्रय मे इजाफा होने से युवा पीढ़ी बर्बाद होने की कागर पर आने लगी हैं। युवाओं, किशोरों का लगभग नियमित मदिरा पान करने से घरों का माहौल बिगड़ने की जहां शुरुआत हो गई है वही शहरवासी भी शहर के युवाओं के भविष्य को लेकर चिंता में नजर आने लगे हैं। सूत्रों के अनुसार इन दिनों नाश के कारोबार मे एक नया मोड आ गया है तथा स्मैक तथा अन्य ऐसे नशीले पदार्थों भी बेचे जाने लगे हैं जिनका उपयोग युवाओं के लिए घातक है। मगर इसके बाद भी बताया जाता हैं कि इन नशीले पदार्थों का पहली बार उपयोग करने के बाद गरीब, युवा इसके आदी हो जाते हैं और इन नशीली चीजों के ना मिलने पर उनका शरीर छट पटाने लगता है। युवा बर्बादी की राह पर कदम बड़ा रहे हैं। शासन प्रशासन और सामाजिक व्यक्तियों को पुलिस का साथ देना चाहिए। अब नशीले पदार्थों पर रोक लगाना जरूरी हो गया है।

समाचार पत्र साप्ताहिक जगत प्रवाह के स्वामित्व एवं अन्य विषयों से संबंधित विवरण घोषणा

फार्म 4 (नियम 8 देखिये)

1. प्रकाशन स्थान	:	भोपाल
2. प्रकाशन अवधि	:	साप्ताहिक
3. मुद्रक का नाम	:	विजया पाठक
नागरिकता	:	भारतीय
पता	:	एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.)
4. प्रकाशक का नाम	:	विजया पाठक
नागरिकता	:	भारतीय
पता	:	एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.)
5. संपादक का नाम	:	विजया पाठक
नागरिकता	:	भारतीय
पता	:	एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.)
6. उन व्यक्ति के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों।	:	विजया पाठक एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.)

मैं विजया पाठक एतद् द्वारा घोषित करती हूं कि ऊपर दिया गया समस्त विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार पूरी तरह सत्य है।

प्रकाशक के हस्ताक्षर

विजया पाठक

दि. 4.03.2025

सम्पादकीय

साहस और स्वाभिमान का प्रतीक रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज

छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के महान और अद्वितीय योद्धा, कुशल रणनीतिकार और दूरदर्शी शासक थे या यह कहा जा सकता है कि अद्भुत शौर्य, अदम्य साहस और स्वाभिमान का दूसरा नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले एक मराठा सरदार थे और माता जीजाबाई धार्मिक और वीरांगना महिला थीं। शिवाजी के व्यक्तित्व और विचारों को आकार देने में उनकी माता का विशेष योगदान रहा। शिवाजी का बचपन साहस और कर्तव्य परायणता की कहानियों के बीच बीता। जीजाबाई ने उन्हें रामायण, महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं से प्रेरणा देने वाली कहानियां सुनाईं, जिससे उनमें धर्म, न्याय और स्वाभिमान का भाव विकसित हुआ। उनका पालन-पोषण मराठा संस्कृति और सैन्य शिक्षा के साथ हुआ। उनकी पहली सैन्य शिक्षा दादा जी कोंडदेव के मार्गदर्शन में हुई।

स्वराज्य स्थापना का सपना- शिवाजी का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र और स्वायत्त शासन की स्थापना करना था। उन्होंने "हिंदवी स्वराज्य" की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए कड़ी मेहनत की। मात्र 16 वर्ष की आयु में उन्होंने तोरणा किले पर कब्जा कर अपने स्वराज्य की नींव रखी। इसके बाद कोंढाना, पुरंदर, राजगढ़ और अन्य किलों पर अधिकार कर उन्होंने मराठा साम्राज्य का विस्तार किया।

सैन्य उपलब्धियां- शिवाजी महाराज ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति को अपनाया, जिसे 'गनिमी कावा' कहा जाता है। उनके इस अनोखे युद्ध कौशल ने मुगलों, आदिलशाही, और निजामशाही जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों को कई बार पराजित किया। 1664 में उन्होंने सूरत पर हमला कर वहां की संपत्ति का उपयोग अपनी सेना को मजबूत करने के लिए किया। 1670 में सिंहगढ़ का वीरता से कब्जा करने का उनका अभियान इतिहास में अमर है।

औरंगजेब के साथ संघर्ष- मुगल सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी को हराने के लिए कई प्रयास किए। 1666 में शिवाजी को आगरा दरबार में बुलाया गया, जहां उन्हें कैद कर लिया गया। लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के बल पर शिवाजी वहां से भागने में सफल रहे। इसके बाद उन्होंने मराठा साम्राज्य को और अधिक संगठित और शक्तिशाली बनाया।

छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक- 1674 में रायगढ़ किले पर शिवाजी का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक हुआ। इस अवसर ने मराठा साम्राज्य को औपचारिक पहचान दी। उन्होंने अपने प्रशासन को न्यायप्रिय और अनुशासित बनाया। कृषि, व्यापार, और राजस्व व्यवस्था में सुधार कर उन्होंने अपने प्रजा का जीवन स्तर ऊंचा किया। शिवाजी महाराज न केवल हिंदुओं के लिए, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखने वाले शासक थे। उन्होंने महिलाओं के प्रति सम्मान का आदर्श स्थापित किया।

सियासी गहमागहमी

शादियों में गिले शिकवे दूर कर मिल रहे गले

राजनीति की बिसात में पक्ष और विपक्ष के नेता भले ही चाहे जितनी खींचतान करें, लेकिन पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में उनमें बहुत ही स्नेह और प्रेम के रंग दिखाई देते हैं। ऐसे ही कुछ रंग दिखाई दे रहे हैं पिछले दिनों प्रदेश के राजनेताओं के घरों में हो रहे वैवाहिक कार्यक्रमों में। पहले शिवराज सिंह चौहान के बेटे के हुए शादी समारोह में पक्ष से लेकर विपक्षी दल के कई प्रमुख नेता शामिल हुए। वहीं पिछले दिनों तुलसी सिलावट के बेटे की हुई शादी में वह सभी भाजपाई नेता भी जमकर ठुमके लगाते नजर आये जो सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल होने पर तुलसी सिलावट को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। यही नहीं कई जगह तो भाजपा और कांग्रेसी नेता एक ही थाली में स्वादिष्ट व्यंजनों के चटकारे लेते भी दिखाई दिये। कुल मिलाकर नेताओं का यह व्यवहार देख एक बात समझ लेना चाहिए कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और।

नये कांग्रेस प्रभारी ने की पटवारी की जमकर खिंचाई

मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भंवर जितेंद्र सिंह की जगह राजस्थान से ही आने वाले हरीश चौधरी को नया प्रभारी बनाया है। जो राहुल गांधी की टीम के अहम हिस्सा माने जाते हैं। ऐसे में एमपी का प्रभार मिलने के बाद अब भोपाल में कांग्रेस पार्टी के अंदर मैराथन बैठकों को दौर चल रहा है। पिछले दिनों हरीश चौधरी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में चौधरी ने पटवारी की कार्यशैली पर असंतोष जाहिर करते हुए दोटूक कहा कि अगर उन्होंने आने वाले कुछ समय में अपनी कार्यशैली में परिवर्तन नहीं किया और कार्यकर्ताओं व नेताओं में समन्वय स्थापित नहीं किया तो पार्टी को इस संबंध में कड़े फैसले ले पड़ेगा। यही नहीं उन्होंने एक बार फिर संगठन में बदलाव होने के संकेत मिले हैं। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में आने वाले दिनों में कई जिलों में जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

अक्सर सबसे अंधकार भरे समय में ही इंसानियत की रोशनी सबसे ज्यादा चमकती है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान कुली भाइयों ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए कई यात्रियों की जान बचाई थी। इसके लिए मैंने देशवासियों की ओर से आज उनका धन्यवाद किया।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi

छिंदवाड़ा में ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है लेकिन सच्चाई यह है कि जनता को पेट्रोल ही नहीं मिल पा रहा।

प्रदेश सरकार तकरीबन हर महीने 5000 करोड़ रुपये कर्ज लेती है, लेकिन आखिर कर्ज का यह पैसा विकास योजनाओं में खर्च नहीं हो रहा है तो कहाँ जा रहा है?

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

छात्र राजनीति से भारत सरकार के प्रमुख पदों पर जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं शिवराज सिंह चौहान

समता पाठक/जगत प्रवाह

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य बने हैं। शिवराज सिंह चौहान अब मोदी कैबिनेट का अहम हिस्सा हैं। विदिशा से छठवीं बार सांसद चुने गए शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में भाजपा के सबसे पुराने और वरिष्ठ नेताओं में एक हैं। शिवराज सिंह चौहान 2024 के लोकसभा चुनाव में विदिशा सीट से भारी मतों के अंतर से विजयी हुए हैं। अगर हम मौजूदा समय में शिवराज सिंह चौहान की राजनीति सफर को देखें तो इनका कद बाकी नेताओं से काफी अलग दिखाई देता है। इन्होंने अपने छात्र जीवन से राजनीति की शुरूआत की थी और अभी तक सियासत के कई अहम पदों पर अपनी सेवा दे चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान का जन्म 5 मार्च 1959 को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के जैत गांव में हुआ था। शिवराज को लेकर कहा जाता है कि जन्म से ही वो बड़े अच्छे वक्ता हैं। सभाओं में भाषण इतनी शानदार तरीके से देते थे कि उनका मुरीद सभी हो जाते। शिवराज महज 13 साल की उम्र यानी साल 1972 में ही आरएसएस का दामन थाम लिया था। शुरू से ही बीजेपी और आरएसएस की छात्र शाखाओं से जुड़ रहे। इन्होंने अपनी पढ़ाई बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र में की। पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से उन्हें स्वर्ण पदक से भी नवाजा जा चुका है।

शिवराज सिंह चौहान को जमीन से जुड़ा हुआ नेता माना जाता है। ये जनता के साथ काफी कनेक्ट रहते हैं, यही वजह है कि राज्य की जनता भी उन्हें बहुत प्यार करती है। ये पूरे देशभर में 'मामा' के नाम से मशहूर हैं। शिवराज एमपी के 4 बार सीएम रह चुके हैं। ये बीजेपी के सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले नेता हैं। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान 5 बार सांसद और 5 बार विधायक रह चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान ने अपना पहला चुनाव बुधनी विधानसभा सीट से साल 1990 में लड़ा था। लेकिन ठीक इसके अगले साल यानी साल 1991 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी आलाकमान ने उन्हें जनरल इलेक्शन में खड़ा किया। दरअसल, इस सीट से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अटल बिहार वाजपेयी सांसद रह चुके हैं। लेकिन 1991 के आम चुनाव में अटल जी ने दो लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, पहला लखनऊ तो दूसरा विदिशा। इसे लेकर अटल बिहारी जी ने कहा था कि जिस सीट पर उन्हें ज्यादा मतों से जीत मिलेगी वो उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। इस चुनाव में अटल जी को लखनऊ सीट से प्रचंड जीत मिली थी।

जबकि विदिशा सीट पर उन्हें थोड़ी कम वोट मिली थी लेकिन जीत दर्ज करने में कामयाब हो गए थे। अपनी बात पर अमल करते हुए अटल जी ने विदिशा लोकसभा सीट छोड़ दी। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने इस सीट पर चुनाव लड़ाने के लिए नेताओं की खोज करने लगे। तमाम खोजबीन के बाद शिवराज सिंह चौहान का नाम का एलान किया गया। विदिशा लोकसभा सीट से शिवराज पहली बार साल 1991 में खड़े हुए और अपनी पहली संसदीय चुनाव में उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की। ये जीत का कारवां चलता रहा। बता दें कि विदिशा लोकसभा सीट से शिवराज सिंह चौहान 1991 के अलावा 1996, 1998, 1999 और 2004 में चुने जा चुके हैं।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा के सामान्य वर्ग होने और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल रखने पर मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी

(पेज 1 का विस्तृत)

मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर एक बार सियासत तेज हो गई है। लंबे समय से चल रहे प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदारों के नाम से पर्दा कब उठेगा यह कह पाना अभी संभव नहीं है। लेकिन सियासी गलियारों से चर्चाएं आ रही हैं उसके अनुसार यह तय माना जा रहा है कि इस बार भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का दावेदार सामान्य वर्ग से ही चुना जाएगा। जाहिर है कि वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व डॉ. वीडी शर्मा के पास है और वह पिछले कुछ समय से एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। ऐसे में लंबे समय से चले आ रहे प्रदेश अध्यक्ष के दावेदारों में डॉ. नरोत्तम मिश्रा प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि डॉ. नरोत्तम मिश्रा मध्यप्रदेश के गृहमंत्री जैसे प्रमुख पद का दायित्व संभाल चुके हैं और इसके अलावा उन्हें अलग-अलग राज्यों में चुनाव का दायित्व भी दिया गया, जिस पर पार्टी की उम्मीद पर वे खरा उतरे। वहीं, अगला नाम यदि सामान्य वर्ग से देखा जाता है तो फिर आता है कैलाश विजयवर्गीय और गोपाल भार्गव का। क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय और गोपाल भार्गव प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व में मंत्री पद का दायित्व संभाल चुके हैं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का ताज नरोत्तम मिश्रा के ऊपर सजने के चांस अधिक नजर आ रहे हैं।

कैलाश विजयवर्गीय भी हो सकते हैं रेस में

कैलाश विजयवर्गीय अमित शाह के करीबियों में माने जाते हैं और प्रिय राजनेताओं में उनका नाम शीर्ष पर है। ऐसे में सामान्य वर्ग का होने पर विजयवर्गीय के सिर पर भी प्रदेश अध्यक्ष का सहरा बांधा जा सकता है।

वीडी शर्मा के वापस आने का चांस कम

वीडी शर्मा को संसद की याचिका समिति में जगह मिलने से उनके दोबारा अध्यक्ष बनने की संभावना कम हो गई हैं। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि पार्टी ने शर्मा को यह पद देकर उन्हें अध्यक्ष पद से दूर रखने का संकेत दे दिया है। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। वे इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं।

सबसे ज्यादा चर्चा में नरोत्तम मिश्रा

गुप्त बैठक के बाद से ही पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। सूत्रों की मानें तो विजयवर्गीय ने शाह के सामने नरोत्तम मिश्रा के नाम का प्रस्ताव रखा है। ऐसी भी खबरें हैं कि पार्टी कैलाश विजयवर्गीय को भी यह मौका दे सकती है। मार्च के पहले हफ्ते तक प्रदेश बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है।

दिल्ली चुनाव में नरोत्तम की रही है बड़ी भूमिका

जाहिर है कि नरोत्तम मिश्रा को विधानसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी ने कोई बड़ी भूमिका नहीं दी। ऐसे में मिश्रा ने भी संगठन में रहकर पार्टी के दायित्वों का निर्वहन किया। दिल्ली चुनाव में पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा पर भरोसा दिखाया और उन्हें अहम जिम्मेदारी दी। अपनी जिम्मेदारी पर मिश्रा बखूबी खरा उतरे और पार्टी ने दिल्ली में फतह हासिल की। यह पहला अवसर नहीं है जब मिश्रा को पार्टी ने इस तरह की कोई बड़ी जिम्मेदारी दी है, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों के चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप चुकी है।

सबको साथ लेकर चलने पर भरोसा रखते हैं नरोत्तम

नरोत्तम मिश्रा के नाम को लेकर चर्चाएं तेज होने का एक बड़ा कारण यह भी है कि नरोत्तम मिश्रा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर सामंजस्य बैठाकर कार्य करने का दमखम रखते हैं। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा के चयन के पीछे दो सबसे बड़े प्रमुख कारण यही है कि पहला वे सामान्य वर्ग से आते हैं और दूसरा सबको साथ लेकर चलने पर विश्वास रखते हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उनका तालमेल बेहतर है। नरोत्तम मिश्रा की सत्ता में पकड़ की बात की जाए तो विगत विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के कद्दावर नेताओं को उनके कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल करवाकर उन्होंने अपना सत्ता चातुर्य और समझ को सबके समक्ष प्रस्तुत किया है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत बनाने दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

(पेज 1 से जारी)

सफल क्रियान्वयन बहुत आवश्यक

छत्तीसगढ़ की अधिकांश आबादी कृषि से जुड़ी है और अतिरिक्त आय के लिए पशुपालन का कार्य भी करती है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की विशेषज्ञता में तैयार पायलट प्रोजेक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार लगभग 5 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 6 जिलों को शामिल किया गया है और सफल क्रियान्वयन के बाद इसे पूरे प्रदेश में विस्तारित किया जाएगा।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती

डेयरी उद्योग के विकास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही, प्रदेशवासियों के पोषण स्तर में भी सुधार होगा, जिससे बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव आएगा।उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के साथ-साथ, प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में वृद्धि और सरप्लस दूध के उपयोग को लेकर ठोस कार्य योजना तैयार की जाए। दूध उत्पादन से जुड़े किसानों और पशुपालकों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए ताकि वे आधुनिक तकनीकों को अपनाकर अपनी आय को बढ़ा सकें। वर्तमान में प्रदेश में प्रतिदिन 58 लाख किलोग्राम दूध का उत्पादन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य दुग्ध संघ की कार्यप्रणाली का गहन अध्ययन करने के बाद, दुग्ध उत्पादन और मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है। प्रदेश में सहकारी समितियों के माध्यम से पशुपालकों को आधुनिक तकनीक और मशीनों से दूध की गुणवत्ता जांच और तत्काल भुगतान की सुविधा प्रदान की जाएगी। बायोगैस और बायो-फर्टिलाइजर प्लांट की स्थापना से पशुपालकों को अतिरिक्त आय के स्रोत बढ़ेंगे, जिससे पर्यावरणीय संतुलन भी बना रहेगा।

डेयरी उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प

पायलट प्रोजेक्ट के सफल क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। डेयरी विकास, पशु उत्पादकता संवर्धन, पशु प्रजनन और पशु पोषण को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक योजना के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की जा रही है। राज्य सरकार किसानों और पशुपालकों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से दुग्ध उत्पादन को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जाए। राज्य सरकार प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

देशी वस्त्र उद्योग में बढ़ी उछाल की उम्मीद

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटन और तकनीक को बढ़ावा देने के बाद अब भारतीय वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने का संकल्प लिया है। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में हुए निवेशकों के सम्मेलन में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को कपास की राजधानी (कॉटन कैप्टिल) कहा है। क्योंकि यहां देश के कुल कार्बनिक कपास का 25 प्रतिशत कपास का उत्पादन होता है। चंदेरी, महेश्वरी और खजुराहो में देशी साड़ियों का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। यह उद्योग सैंकड़ों साल से ज्ञान परंपरा और देशी उपकरणों के माध्यम से गतिशील है। इनमें पर्याप्त पूंजी निवेश के साथ तकनीक आधारित आधुनिकीकरण होता है तो उत्पादन के साथ इनकी बिक्री के लिए भी वैश्विक बाजार मिलेगा। ऋग्वेद समेत धर्म व इतिहास के ग्रंथों को खंगाले तो पता चलता है कि भारत कपास के उत्पादन से लेकर वस्त्रों के निर्माण और रंगाई में अग्रणी देश रहा है। इसी कारण यहां परिधानों के पहनने और ओढ़ने के अनेक तरीके प्रचलन में रहे हैं। शैल-चित्रों से लेकर सिंधु घाटी की सभ्यता और मंदिरों की मूर्तियों में स्त्री-पुरुष व बच्चे अनेक प्रकार के वस्त्र पहने हुए चित्रित हैं।

ऋग्वेद तथा अन्य संस्कृत ग्रंथों में भी वस्त्रों का विवरण है। इन ग्रंथों के पात्र विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहने हुए वर्णित किए गए हैं। भारत में भूगोल, जलवायु, ऋतु, राशि, जाति और धर्म के आधार पर भी वस्त्रों के पहनने का विवरण मिलते हैं। उत्सव, खेल, नृत्य और युद्ध के समय अलग-अलग तरह के परिधान पहने जाते थे। परिणय संस्कार के समय पहने जाने वाले वस्त्रों की आभा विलक्षण रही है। भारत में कपास उत्पादन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। कपास से चरखे पर सूत कातकर कारीगर वस्त्र बनाते थे। कपास से वस्त्र निर्माण की परंपरा पांच हजार साल से भी ज्यादा पुरानी है। धागों और वस्त्रों को रंगने की तकनीकी क्षमता में भी कारीगर दक्ष थे। इनमें गोटे से कढ़ाई भी की जाती थी। साफ है, भारत विविध प्रकार के कपड़े बनाने व पहनने का आदी प्राचीन समय से ही रहा है इसे सूती वस्त्र उद्योग के नाम से पहचान मिली हुई है। यह उद्योग अपनी समग्र मूल्य श्रृंखला, स्थानीय कच्ची सम्पदा की उपलब्धता तथा निर्माण कला में दक्ष होने के कारण विश्व के बड़े वस्त्र उद्योगों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस उद्योग की विशिष्टता इसके व्यापक विस्तार में रही है। एक तरफ वस्त्रों के निर्माण में लगे सूक्ष्म हस्त शिल्पी हैं, तो दूसरी तरफ आधुनिक मशीनों से वस्त्र बनाने वाले पूंजीपति हैं।

व्यापार के बहाने अंग्रेजों की जब इस उद्योग पर नजर पड़ी तो उन्होंने इस परंपरागत हस्तशिल्प को नष्ट कर ब्रिटेन से लाई गई मशीनों से कपड़े का निर्माण शुरू कर दिया। 1818 में कलकत्ता के पास पहला सूती कपड़ा उद्योग फोर्ट ग्लस्टर में लगाया गया था। इसके बाद 1854 में बंबई में बॉम्बे स्पिनिंग मिल की स्थापना की गई। आज करीब 3400 वस्त्र उद्योगों में लगे 10 करोड़ लोग आजीविका चलाते हैं। इनके अलावा हथकरघा, हस्तशिल्प, छोटे स्तर की विद्युत-करघा इकाइयां और परंपरागत रूप से भी बड़ी मात्रा में वस्त्रों का उत्पादन होता है। ये लघु व घरेलू उद्योग भी लाखों लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजी-रोटी उपलब्ध कराते हैं। इस उद्योग में कपास, प्राकृतिक व मानव निर्मित फाइबर, रेशम आधारित वस्त्र और बुने हुए परिधान शामिल हैं। भारत के कुल निर्यात में वस्त्रों की 4.5 प्रतिशत भागीदारी है। निर्यात से होने वाली कुल आमदनी में वस्त्रों का योगदान 15 प्रतिशत है। हालांकि विदेशी वस्त्रों के आयात ने इस देशी उद्योग को वर्तमान में कमजोर किया हुआ है। निर्यात में भी कमी आई है। बांग्लादेश और वियतनाम ने वस्त्र-निर्यात में भारत को पीछे धकेल दिया है। अतएव वस्त्र उद्योग के हालात वैसे ही बनते जा रहे हैं, जैसे फिरंगी हुकूमत के दौरान थे। इसलिए इस उद्योग में आर्थिक निवेश की वाकई जरूरत है।

मध्यप्रदेश पूर्व से ही वस्त्र-निर्माण में अग्रणी रहा है। ग्वालियर में जेसी मिल, इंदौर में हुकुमचंद्र, उज्जैन में विनोद मिल जैसे बड़े वस्त्र-उद्योग सांतवें दशक तक अस्तित्व में थे। लेकिन कर्मचारी संगठनों की हड़तालों ने इन वस्त्र उद्योगों को लगभग मटियामेट कर दिया। नागदा में जरूर बिड़ला का वस्त्र उद्योग हैं। हालांकि हाथ के चरखे से आज भी चंदेरी और महेश्वर में बड़े पैमाने पर साड़ियों का निर्माण हो रहा है। असली चंदेरी साड़ी पर तो जीआई टैग लगा होता है। जो प्रमाणित करता है कि यह टैग साड़ी की मूल उत्पत्ति और गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। इससे नकली चंदेरी साड़ी की खरीद से ग्राहक बच जाता है। अब ग्वालियर में आर्य प्रताप सिंह ने वैदिक विज्ञान आधारित वस्त्रों का निर्माण शुरू किया है। आजकल खासतौर से युवाओं में वास्तु और ज्योतिष के प्रति आकर्षण है। इसी नजरिए से वैदिक ज्योतिष, ग्रह और नक्षत्र वाले प्रतीकों के परिधानों का निर्माण शुरू किया है। इनकी कीमत 80,000 रुपए से लेकर 04 लाख रुपय तक है। ग्वालियर के ही कंप्यूटर साइंस इंजीनियर एवं गॉड कंपनी के सीईओ आर्यप्रताप सिंह का कहना है कि हम ग्राहक का डेटा प्राप्त कर जन्मतिथि, स्थान, समय और हथेलियों की रेखाओं के आधार पर परिधान तैयार करते हैं। इन्हें रंग, रत्न, धातु के राशि पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुसार तैयार किया जाता है। हम अपने परिधानों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग सोशल मीडिया, वेबसाइट और इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से कर रहे हैं। आर्यप्रताप को इस तरह के वस्त्र निर्माण करने की प्रेरणा रामायण पढ़ने और रामायण पर बने फिल्म एवं धरावाहिकों से मिली है।

यह हमारा अज्ञानता है कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में पश्चिम अग्रणी देशों में आते हैं, जबकि हकीकत यह थी कि हम पश्चिम में खासतौर से ब्रिटेन से बहुत आगे थे। जब ब्रिटेन हमारे कपड़ा उद्योग पर अतिक्रमण कर रहा था, तब हमारे यहां 2400 और 2500 काउंट के महीन धागे बनाने में जुलाहे निपुण थे, केवल एक ग्रेन में 29 गज लंबे धागे हमारे कारीगर बना लिया करते थे। जबकि आज हम जिस कम्प्यूटराइज्ड उन्नत व आधुनिकतम तकनीक की बात करते हैं, उसके जरिए भी 400 से 600 काउंट तक पतले धागे बनाया जाना संभव हो पा रहा है। मुर्शिदाबाद में 2400 से लेकर 2500 तक के महीन धागे बनाए जाते थे। कारीगरों की इस दक्षता को नष्ट करने के लिए अंग्रेजों द्वारा निर्ममतापूर्वक उनके अंगूठे काट दिए गए थे। उनकी इस दुष्टता के बाद भारत में ब्रिटेन के कपड़ा उद्योग को स्थापित करने का मार्ग खुल पाया था। मुर्शिदाबाद के कारीगरों की यह तकनीक किसी किताब में परिभाषित नहीं थी, किंतु शिल्पकारों के दिमाग में यह तकनीकी कुशलता ज्ञान-परंपरा और घरेलू प्रशिक्षण के माध्यम से बैठा दी जाती थी।

ज्ञान परंपरा से जुड़ी उत्पादन व्यवस्था जो भारतीय व्यापार एवं समृद्धि के मूल आधार थे, वे सब अंग्रेजों के दमन और अत्याचार के दायरे में आते चले गए। इन पर किस बेरहमी से शिकंजा कसा गया, इनके उदाहरण अंग्रेजों द्वारा ही लिखे रोजनामचों में मिलते हैं। जो कपड़ा सूरत से विलायत भेजा जाता था, वह जुलाहों से जबरन प्राप्त किया जाता था। यहां तक कि उन पर निर्मम अत्याचार भी किए जाते थे। यदि जुलाहे समय पर पूरा काम नहीं कर पाते थे तो उस माल पर भारी जुर्माना भी ठोक दिया जाता था। कंपनी बुनकरों को माल का इतना कम दाम देती थी कि यदि यही माल बुनकर डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी या अरब सौदागरों को देते तो कहीं ज्यादा मूल्य मिलता। जुलाहों को इस हद विवश किया गया कि वे यदि इस धंधे से बाहर आना चाहें तो उस पर नियम बनाकर प्रतिबंध लगा दिया गया। यहां तक की जुलाहों की फौज में भर्ती पर रोक लगा दी गई। उन्हें दूसरे शहर जाकर भी काम-धंधा करने की अनुमति नहीं थी। चोरी-छिपे कोई जुलाहा चला भी जाता तो पकड़ में आने पर या स्वेच्छा से वापस आने पर उसे अमानवीय यातनाएं दी जाती थीं।

कंपनी का यही दुराचरण बंगाल के बुनकरों के साथ रहा था। 1793 में बंगाल की अंग्रेजी कंपनी ने एक कानून पारित कराया, जिसके अनुसार कोई जुलाहा, जिसे कंपनी का कुछ भी धन देना हो या जो किसी तरह कंपनी के कपड़ा व्यापार से जुड़ा हो, वह आजीवन कंपनी का काम नहीं छोड़ सकता था, न किसी दूसरे के साथ काम कर सकता था और न ही खुद अपने लिए काम कर सकता था। इस नियम से देश भर के जुलाहे कंपनी के गुलाम बनकर रह गए। यदि कोई जुलाहा समय पर पूरा काम नहीं कर पाता था या वादाखिलाफी करता था, तो उसका कच्चा माल तो जब्त कर ही लिया जाता था, उसे कारागार तक में डाल दिया जाता था। अत्याचार की यही पराकाष्ठा बंगाल के रेशम उत्पादकों के साथ बरती गई।

हमारे ही शिल्पकार और हमारी ही धरती से उपजे कपास से बने वस्त्रों के कारोबार से अंग्रेजों ने उस जमाने में देश को कितना लूटा यह जानकर आश्चर्य होता है। चार्ल्स ट्रेविलियन ने 1884 में प्रकाशित अपने रोजनामचे में लिखा है, '1816 में जितना सूती कपड़ा बंगाल से विदेशों को भेजा गया उसका मूल्य 01 करोड़ 65 लाख 94 हजार 380 रुपए था। इसके बाद यह घटकर 1832 में मात्र 8 लाख 32 हजार 891 रुपए रह गया। इसके विपरीत ब्रिटेन का बना हुआ जो कपड़ा बंगाल में आया, उसका मूल्य 1814 में केवल 45 हजार रुपए था, जिसकी खपत 1816 में बढ़कर 3 लाख 17 हजार 602 रुपए हो गई। 1828 में यही खपत बढ़कर 79 लाख 96 हजार 383 रुपए हो गई। भारत वस्त्र निर्माण में इतना सक्षम देश था कि उसे 1823 तक एक गज सूत भी विदेश से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, किंतु 1828 में करीब 80 लाख कपड़े के अतिरिक्त 35 लाख 22 हजार 640 रुपए का सूत ब्रिटेन से बंगाल आया। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो देशी वस्त्र बुनकर और कपास व सूत उत्पादक किसान करीब इस व्यवसाय से 1 करोड़ 80 लाख पूंजी का वार्षिक उत्पादन किया करते थे, उनके आर्थिक स्त्रोत छिनने के बाद वे किस बदहाली में रहे होंगे? अतएव वस्त्र उद्योग में निवेश के प्रयास न केवल उस उद्योग में खुशहाली लाएगी, बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार भी उपलब्ध कराएगी।

एम्स भोपाल ने 7वां जन औषधि दिवस सप्ताह मनाया

-समता पाठक

जगत प्रवाह. भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में संस्थान 01 मार्च से 07 मार्च 2025 तक 7वां जन औषधि दिवस सप्ताह मनाएगा। इस सप्ताह के दौरान, जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं के फायदों और उनकी उपलब्धता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह पहल भारत सरकार की प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) के तहत की जा रही है, जिसका उद्देश्य आम जनता को किफायती दवाएं उपलब्ध कराना और जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है।

जायसवाल परिवार द्वारा खिचड़ी प्रसाद एवं रुद्राक्ष का वितरण

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। नगर के प्रसिद्ध प्राचीन शंकर मंदिर पर महाशिवरात्रि महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जायसवाल परिवार द्वारा शिव अभिषेक के बाद खिचड़ी प्रसाद एवं 05 हजार रुद्राक्ष वितरण कराए गए। यह रुद्राक्ष नेपाल के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर से लाए गए थे। उन्हें अभिमंत्रित कराया गया। परिवार के युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष राहुल जायसवाल, अरूण कुमार जायसवाल व पुनीत जायसवाल पार्षद वार्ड नम्बर 10 टिमरनी ने समस्त जनता से अनुरोध किया था कि शिवभक्त धर्म प्रेमी जनता अधिक से अधिक संख्या में आकर प्रसादी व रुद्राक्ष ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित करें। इस मौके पर अपार श्रद्धालुओं ने प्राचीन शंकर मंदिर पर पूजा अर्चना की और जायसवाल परिवार की ओर से भेंट किए गए रुद्राक्ष प्राप्त किये। इस दौरान श्री प्राचीन सिद्ध हनुमान सेवा समिति और जायसवाल परिवार के मुखिया अरुण कुमार जायसवाल ने सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया।

आज की बात

प्रवीण कक्कड़

स्वतंत्र लेखक

भगोरियाः प्रेम, परंपरा और उल्लास का अद्भुत संगम

बात करीब चार दशक पहले की है। पुलिस सेवा में ज्वाइन होने के बाद मेरी पोस्टिंग आदिवासी अंचल झाबुआ में हुई। यहां आदिवासी संस्कृति को बहुत करीब से देखने का अवसर मिला। विशेष रूप से होली के पहले होने वाले भगोरिया के दौरान तो आदिवासी समाज का उत्साह देखते ही बनता था। आदिवासी अंचलों में विभिन्न पोस्टिंग के दौरान हुए अनुभवों के आधार पर कह सकता हूं कि आदिवासी समाज एक प्रकृतिप्रेमी समाज है, जो मौसम की विभिन्न ऋतुओं के अनुसार अपने अलग-अलग त्यौहार मनाता है। आदिवासी समाज की विशेष वेशभूषा, व्यंजन और लोकगीत व नृत्य की रौनक भगोरिया के मेलों में अनूठी झलक दिखती है। होली के रंगों में रंगने से पहले, आदिवासी समाज भगोरिया के जीवंत उत्सव में डूब जाता है। मालवा और निमाड़ की पहाड़ियों और जंगलों में, यह पर्व युवाओं के दिल में उमंग और उत्साह का संचार करता है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि आदिवासी संस्कृति की जीवंत अभिव्यक्ति है, जहाँ परंपरा और आधुनिकता का अनूठा संगम देखने को मिलता है। भगोरिया में हर तरफ रंगों की बौछार होती है। गुड़ की जलेबी, भजिये, खारिये, पान, कुल्फी, केले और अन्य स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू हवा में तैरती है। आदिवासी संस्कृति के प्रतीक गोदना (टैटू) युवाओं के शरीर पर सजते हैं। जीप, छोटे ट्रक, दुपहिया वाहन और बैलगाड़ियों पर सवार होकर, रंग-बिरंगे परिधानों में सजे-धजे आदिवासी युवक-युवतियाँ भगोरिया मेलों में पहुँचते हैं।

जोड़ता है और हमें हमारी समृद्ध विरासत की याद दिलाता है।

प्रेम का अनोखा इजहार

भगोरिया में प्रेम का इजहार करने का तरीका बेहद खास है। यहाँ युवक-युवतियाँ सज-धज कर अपने जीवनसाथी की तलाश में आते हैं। जब कोई लड़का किसी लड़की को पान खाने के लिए देता है और लड़की उसे स्वीकार कर लेती है, तो इसे उनकी सहमति का प्रतीक माना जाता है। फिर लड़का लड़की को लेकर मेले से भाग जाता है। इसी तरह, अगर कोई लड़का किसी लड़की के गाल पर गुलाबी रंग लगाता है और लड़की भी बदले में लड़के के गाल पर रंग लगा देती है, तो इसे भी रिश्ते की स्वीकृति माना जाता है।

मांदल की थाप और लोकगीतों की गूँज

भगोरिया में युवतियाँ रंग-बिरंगे कपड़े और आभूषण पहनकर आती हैं। मांदल की थाप पर लोकगीत गाते हुए आदिवासी जमकर नृत्य करते हैं। लोक संस्कृति के पारंपरिक गीत माहौल में एक अलग ही समां बांध देते हैं। हरे-भरे पेड़ों के बीच प्रकृति और संस्कृति का यह मिलन मन को मोह लेता है।

एक ऐतिहासिक विरासत

भगोरिया का इतिहास राजा भोज के समय से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि उस समय दो भील राजाओं, कासूमार और बालून ने अपनी राजधानी भागोर में विशाल मेले का आयोजन किया था। धीरे-धीरे, आसपास के अन्य भील राजाओं ने भी इसका अनुसरण करना शुरू कर दिया और इस तरह हाट और मेलों को भगोरिया कहा जाने लगा।

आधुनिकता का प्रभाव

हालाँकि, हाल के वर्षों में शिक्षित युवा वर्ग में भगोरिया के माध्यम से जीवनसाथी चुनने का चलन कम हो रहा है। आधुनिक शिक्षा और बदलते सामाजिक मानदंडों के कारण, युवा अब अपने जीवनसाथी का चयन करने के लिए अलग तरीकों को अपना रहे हैं।

एक सांस्कृतिक धरोहर

भगोरिया सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि आदिवासी संस्कृति की एक अनमोल धरोहर है। यह प्रेम, परंपरा और उल्लास का एक ऐसा संगम है, जो आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। निमाड़ और मालवा के बाजारों में भगोरिया उत्सव को देखने के लिए देश-विदेश से लोग आते हैं। यह पर्व हमें हमारी सांस्कृतिक जड़ों से

सचिव नहीं रहते पंचायत मुख्यालय पर, सरपंच सहित पंचों ने की कलेक्टर से शिकायत

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह. देवरी खास। देवरी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रायखेडा में पंचायत सचिव दीपक खटीक पंचायत मुख्यालय पर नहीं रहते जिससे ग्रामीणों की समस्याएं नहीं सुन पाते और ग्रामीणों को शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता। इस संबंध में सरपंच सहित पंचों द्वारा 25/02/2025 को जिला पंचायत सीईओ एवं जिला कलेक्टर को लिखित रूप से शिकायती पत्र सौंपा। गौरतलब है कि पिछले दिनों सचिव दीपक खटीक की पदस्थापना ग्राम पंचायत भरई में थी। तब भी इन्हें पंचायत मुख्यालय पर न रहने के चलते जिला पंचायत सीईओ के निर्देश पर देवरी मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा निलंबित किया गया था। उसके बाद भी सचक नहीं ले रहा। लापरवाह सचिव इन पर कार्यवाही की मांग को लेकर शिकायती पर सौंपा। वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत रायखेड़ा में इन दिनों फर्जी बिल भुगतान का दौर जारी है। तीन की चीज तेरा के बिल भुगतान किए जा रहे है। उसकी जांच होनी चाहिए। इसी के चलते दो वर्ष पूर्व, विधायक निधि के द्वारा ग्राम पंचायत रायखेड़ा के भोरया में सरपंच के घर के पीछे पीएचई विभाग द्वारा नलकूप बोरवेल का खनन कराया गया था और उस बोरवेल के गड्ढे में पीएचई विभाग द्वारा सब्मर्शियल मोटर डाली गई थी और पानी की सप्लाई चालू हुई थी जिसमें ग्रामीणों को पानी की समस्या से निजात मिली थी। उसके बाद तत्कालीन सचिव द्वारा फर्जी रूप से उसी बोरवेल गड्ढा में सरपंच के घर के पीछे सब्मर्शियल मोटर खरीदी का फर्जी बिल लगाकर 21/11/2024 को 37386 राशि का बिल भुगतान कराया गया। जहा पर न तो नए रूप में कोई सब्मर्सियल मोटर नहीं खरीदी गई। उसको लेकर फर्जीवाड़ा कर बिल का भुगतान कराया गया है जिसकी जांच होनी चाहिए और कार्यवाही होना चाहिए।

युवती से दुष्कर्म के आरोप में मुंहबोले रिश्तेदार को किया गिरफ्तार

-कैलाशचंद्र जैन

जगत प्रवाह. छिंदवा। चैनपुरा निवासी 19 वर्षीय युवती ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह घर के पास की दुकान पर सामान लेने गई थी। वहां पर उसे मनमोहन वंशकार मिला, जो उसके दूर के रिश्ते में लगता था। मनमोहन ने युवती को अपने साथ चलने के लिए कहा, जिस पर युवती सहमत हो गई। मनमोहन उसे दुकान के पास स्थित एक खुले दालान में ले गया, जहां पहले से ही गौतम वंशकार शराब की तीन क्वार्टर लेकर खड़ा था। मनमोहन ने युवती को गौतम के पास छोड़ दिया और वहां से चला गया। इसके बाद गौतम ने जबरदस्ती युवती को शराब पिलाई और उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ समय बाद, मनमोहन ने युवती से झूठ कहा कि उसके माता-पिता वहां आ गए हैं, जिससे घबराकर गौतम वहां से भाग गया। युवती ने घर पहुंचकर अपने माता-पिता को पूरी घटना बताई, जिसके बाद वे थाना पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता के बयान के आधार पर थाना लटेरी द्वारा

महिला अधिकारी उपनिरीक्षक गोसिया सुल्तान को रिपोर्ट लेखबद्ध करने हेतु भेजा गया। शिकायत के आधार पर आरोपी गौतम वंशकार और मनमोहन वंशकार के विरुद्ध अपराध क्रमांक 72/25, धारा 70(1) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई। लटेरी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु एक विशेष टीम का गठन किया। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चैनपुरा के जंगल में दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को न्यायालय लटेरी में पेश किया गया, जहां से उन्हें उप-जेल लटेरी में भेज दिया गया। पीड़िता को पुलिस कार्यवाही के उपरांत परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेपन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)